


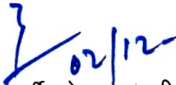
तेजाराम पुत्र भूशराम जाति जाट
निवासी सरेली की ढाणी, डण्डाली
तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

भलाराम पुत्र राणाराम जाति जाट
निवासी सरेली की ढाणी, डण्डाली
तहसील सिणधरी जिला बालोतरा व
अन्य

बनाम

मुकदमा सं. 187 / 2024

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
02.12.2024	<p>महोदय</p> <p>यह आवेदन प्रार्थी तेजाराम की ओर से मुल पत्रावली के निस्तारण से पूर्व हुए नेखमबंदी आदेश को निरस्त करते के तहत धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पेश किया गया है।</p> <ol style="list-style-type: none">1.कोर्ट फीस पूर्ण है।2.वाछित दस्तावेज सलंगन/पूर्ण है।3.प्रस्तुत आवेदन पत्र पर प्रार्थीगण को सुना जाना है। <p>अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ </p>	
02.12.2024	<p>सहायक कलक्टर (एस.डी.एम)सिणधरी </p> <p>यह आवेदन प्रार्थी तेजाराम की ओर से मुल पत्रावली के निस्तारण से पूर्व हुए नेखमबंदी आदेश को निरस्त करते के साथ ही धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रस्तुत आवेदन के तथ्यों पर प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया।</p> <p>चूंकि हस्तगत आवेदन के जरिये प्रार्थी द्वारा राजस्व आवेदन सं. 93/2023 अनवान लुम्भाराम बनाम भीखा में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2023 को निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 रा.भू.रा. अधि. 1956 के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही निरस्त किये जाने की इस्तदुआ चाही गई है।</p> <p>प्रकरण के सलंगन दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन में पाया गया कि राजस्व वाद सं. 127/2016 राणा बनाम तेजाराम में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2020 के जरिये पक्षकारान के मध्य विभाजन का वाद न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित किया गया। उक्त निर्णय की पालना में राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद के जरिये प्रार्थीगण द्वारा नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत किया जो, दिनांक 19.09.2024 को निर्णीत हुआ। इसी</p>	

उपरखण्ड अधिकारी
सिणधरी



बीच निर्णीत वाद सं. 127/2016 के प्रतिवादीगण द्वारा अपनी ओर से माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के समक्ष दायर अपील में अपने निर्णय दिनांक 07.04.2021 के जरिये इस न्यायालय में पुनः सुनवाई करते हुए बाइ मिट्स एण्ड बारण्ड विभाजन प्रस्ताव मिजवाने के निर्देशों सहित प्रकरण रिमाण्ड किया गया, जिस पर पक्षकारान की विधिवत सुनवाई बाद दिनांक 16.01.2024 को निर्णीत किया गया। इस प्रकार मूल प्रकरण सं. 127/2016 के पूर्व में पारित निर्णय के विरुद्ध रिमाण्ड प्रकरण के पुनः निस्तारण के मध्य नेखमबंदी के प्रकरण के निस्तारण की कार्यवाही के दौरान किसी भी पक्षकार द्वारा इस संबंध में कोई प्रकरण जैरकार होने अथवा कोई स्थगन इत्यादि होने की जानकारी न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाये जाने से नेखमबंदी के प्रकरण का विधिवत निस्तारण किया गया। चूंकि इस प्रकार बाद विधिवत सुनवाई के निस्तारित प्रकरण में अब नये सिरे से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते एकतरफा कार्यवाही निरस्त किये जाने के तथ्य चस्प नहीं होते हैं। जहां तक निस्तारित प्रकरण को पुनः सुने जाने अथवा उसके संबंध में की गई कार्यवाही के बाद पारित किसी आदेश को निरस्त किये जाने की इस्तदुआ सहित प्रस्तुत प्रकरण में जब तक किसी सक्षम न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जाती अथवा उसके निरस्त या अपास्त किये जाने के आदेश पारीत नहीं किये जाते हैं, तब तक उसी न्यायालय द्वारा एक ही प्रकरण जो निस्तारित हो चुका हो, पर पुनः सुने जाने के प्रावधान विधि के परिप्रेक्ष्य में न्यायसंगत नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण श्रवणाधिकार के बिन्दु पर खारिज किया जाकर प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश के संबंध में असतुष्ट होने पर आलोच्य आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

उपरखण्ड अधिकारी
मिणधरी